एक नजर में

ट्राले की टक्कर से महिला की मौत, दो घायल

धार. मध्यप्रदेश के धार जिले की धरमपुरी तहसील में कुंदा फाटे पर आज शनिवार सुबह हुए भीषण सड़क दुर्घटना में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. महिला मायके से ससुराल लौट रही थी, तभी तेज रफ्तार ट्राला काल बनकर आया. पुलिस सूत्रों के अनुसार धामनोद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धानी और दूधी के बीच एबी रोड स्थित राजराजेश्वरी मंदिर के सामने सुबह लगभग 9:30 बजे मोटरसाइकिल सवार परिवार को पीछे से आ रहे तेज गति ट्राले ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों सड़क पर गिर पड़े.

साइबर ठगी के 20 आरोपी गिरफ्तार

शिवपुरी. मध्यप्रदेश की शिवपुरी पुलिस ने अश्लील वीडियो दिखाकर गिरफ्तार करने का डर दिखाकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 20 सदस्यों को गिरफ्तार करके उनके पास से नगद राशि, मोबाइल फोन तथा चार पहिया एवं दो पहिया वाहन एवं अन्य सामान बरामद किया है. पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ ने आज दोपहर बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में जिले के करेरा एवं पिछोर क्षेत्र के निवासी आरोपी हैं, जो संगठित रूप से साइबर ठगी कर रहे थे. करेरा एसडीओपी आयुष जाखड़ एवं पिछोर एसडीओपी प्रशांत शर्मा को टीम बनाकर इस कार्य में लगाया गया था.

प्रोजेक्ट चीता : दुनिया का सफल प्रोजेक्ट

- 28 तक आएंगे बोत्सवना से 8 और चीते : सीएम
- चीता प्रोजेक्ट ने तीन वर्ष पूरे किए

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 21 फरवरी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में मप्र में चीता पुनर्स्थापन का प्रोजेक्ट चीता दुनिया विश्व का सबसे सफल प्रोजेक्ट है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कूनो में चीतों की सफल बसाहट पर खुशी जताते हुए कहा कि 28 फरवरी तक बोत्सवाना से 8 और चीते लाये जायेंगे. यह परियोजना प्रकृति से प्रगति का संदेश है.

भारत में विलुप्त हो चुके चीते के पुनर्स्थापन का ऐतिहासिक प्रयास, प्रोजेक्ट चीता, ने अपने तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं. सितंबर 2022 में शुरू हुई यह वन्य जीव संरक्षण यात्रा सफलता के स्वर्णिम सोपान चढ़ चुकी है. नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों ने भारतीय धरती पर खुद को अनुकूलित कर लिया है. कूनो और गांधी सागर अभयारण्य में उनकी दूसरी पीढ़ी के शावकों के निर्भय फर्राटों ने सिद्ध कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कल्पना को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में हुए प्रयासों ने साकार कर दिया है. भारत के अभयारण्यों में फर्राटे भरते चीतों की रफ्तार भविष्य में जैव-विविधता संरक्षण की एक प्रेरक मिसाल बन रही है.

ऐतिहासिक शुभारंभ से सशक्त स्थापना :

नामीबिया से 17 सितंबर 2022 को 8 चीतों का आगमन हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कूनो अभयारण्य के संरक्षित बाड़ों में छोड़ कर पुनर्स्थापना परियोजना का शुभारंभ किया. दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते 18 फरवरी 2023 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गये. दक्षिण अफ्रीका से आये 12 में से 8 चीते वर्तमान में कूनो अभयारण्य में पूर्णत: स्थापित होकर स्वयं को वर्तमान आवास की परिस्थितियों में ढाल चुके हैं और पूरी तरह स्वस्थ हैं. इनमें से 3 चीते गांधी सागर अभयारण्य में स्थानांतरित किए गए हैं.

> दक्षिण अफ्रीकी माताओं से जन्मे 10 शावक वर्तमान में जीवित और स्वस्थ हैं. भारत में जन्मी पहली वयस्क मादा चीता मुखी 'ने भी 5 शावकों को जन्म दिया है. यह इस बात का प्रमाण है कि भारत में चीता पुनर्स्थापन परियोजना अब शैशवास्था से आगे बढ़कर स्थायी स्थापना और प्रजनन के चरण में प्रवेश कर युवा हो चुकी है. गामिनी दूसरी बार मां बनी है. उसकी पहली खेप में 3 स्वस्थ सब-एडल्ट शावक हैं और हाल ही में उसने 3 नए शावकों को जन्म दिया है.

प्रदेश में चार दिन तक आंधी-बारिश के आसार

दक्षिण-पूर्वी जिलों में ज्यादा असर

भोपाल, 21 फरवरी. मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. प्रदेश के कई हिस्सों में अगले चार दिन तक तेज हवा और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

बीते 24 घंटों में कई जिलों में वर्षा दर्ज की गई, जबकि कुछ स्थानों पर आंधी और ओले भी गिरे. राजधानी भोपाल में दिनभर बादल छाए रहे और रात में हल्की बूंदाबांदी हुई. मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और मऊगंज में बारिश के आसार हैं. वहीं इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर सहित अन्य शहरों में बादल छाए रहने की संभावना है.

23 और 24 फरवरी को एक नया मौसमी तंत्र सक्रिय होने से दक्षिण-पूर्वी जिलों में असर ज्यादा दिख सकता है. 23 फरवरी को नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में बारिश की संभावना जताई गई है. 24 फरवरी को सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भी बादल बरस सकते हैं.

> पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के मौसम को प्रभावित करेगा. लगातार बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है. रतलाम, शाजापुर और उज्जैन समेत कई जिलों में तेज हवाओं से गेहूं की खड़ी फसल झुक गई है. पिछले तीन दिनों में करीब 25 जिलों में फसलों को नुकसान की आशंका है. प्रशासन ने सर्वे शुरू कर दिया है और राजस्व अमला गांव-गांव पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रहा है. फरवरी में यह चौथी बार है जब आंधी-बारिश का दौर देखने को मिल रहा है.

सीएम हेल्पलाइन में 3 बार अव्वल सिंगरौली पुलिस

सिंगरौली. सिंगरौली पुलिस ने सीएम हेल्पलाइन 181 की शिकायतों के निराकरण में एक बार फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. 21 फरवरी को जारी जिलेवार ग्रेडिंग में सिंगरौली जिले ने कुल 91.49 प्रतिशत वेटेज स्कोर के साथ ए ग्रेडिंग हासिल की. इसी के साथ जिला लगातार तीसरी बार प्रदेश के प्रथम समूह में शीर्ष स्थान पर रहा. यह उपलब्धि पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन गौरव राजपूत के निर्देशन में संभव हो सकी. जनवरी 2026 में कुल 1205 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 1128 शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण किया गया.

मंत्रालय के गलियारे से

कन्हैया लोधी

आखिरकार बदल ही गए

मंत्रालय में एक एसीएस स्तर के अधिकारी लंबे समय से विभाग में जमे थे. विभाग में उनकी इतनी तूती बोलती थी कि उनकी मर्जी के बगैर जैसे पत्ता भी न खड़के. उनके दखल के चलते विभागाध्यक्ष कार्यालय के मुखिया भी स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन पिछले दिनों जो सूची आई, उससे पूरा विभागाध्यक्ष कार्यालय के साथ ही एक बड़े कॉडर ने भी राहत की सांस ली. अब विभाग में ऐसे अफसर आए हैं, जिनको परमसंतोषी माना जाता है. ये साहब बड़े कूल माने जाते हैं. कुल मिलाकर ये कि लंबे समय से जो कॉडर तबादले की कामना कर रहा था, वे साहब आखिरकार बदल ही गए.

नदारत रहे साहब

विधानसभा में पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही थी, मामला एक बड़े साहब के विभाग से जुड़ा हुआ था, सामान्य तौर पर विभाग से जुड़े किसी विषय पर चर्चा हो, तो विभाग के अफसर मौजूद रहते हैं, लेकिन विभाग के आला अफसर सदन में रहने के बजाय राजधानी से ही बाहर रहने को तवज्जो दी. बताया जा रहा है कि उन्हें राजधानी से बाहर होने वाली चमक-धमक का कार्यक्रम ज्यादा रास आया, ऐसे में उन्होंने मातहतों के भरोसे छोड़कर रवानगी दे दी. उनके नदारत रहने के मामले को माननीयों ने भी नोटिस किया.

बर्निंग सब्जेक्ट अब हाशिये

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से लोगों की मौत का मामला इस बजट सत्र के दौरान विपक्ष के लिए सबसे बर्निंग सब्जेक्ट था, अब इस मामले में जहां कई सदस्यों के सवालों के जवाब आ गए तो वहीं दूसरी तरफ सदन में चर्चा भी हो गई. विपक्ष ने इस मामले में वाकआउट भी कर दिया था, अब ऐसे समय जब सत्र अगले सप्ताह में प्रवेश कर रहा है, ये बर्निंग सब्जेक्ट भी विपक्ष के पास से आउट हो गया है. अब सत्र के बाकी दिनों में इस मामले में ज्यादा गर्माहट सदन में देखने नहीं मिलेगी, ये तय है.

मंत्रीजी की प्राथमिकता

प्रदेश के कद्दावर मंत्रीजी की प्राथमिकता बदली हुई है. ये साहब फिलहाल अक्सर ही सुर्खियों में बने हुए हैं, तनाव की भी कमी नहीं है. ऐसे में उन्होंने इस तनाव को रिलीज करने का बढ़िया नुस्खा खोज निकाला है. ये साहब भोपाल के बजाय अपने क्षेत्र में अपने घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, वहां परिवार गुलजार है. देर रात नाती-पोतों के साथ क्रिकेट का लुत्फ उठाते हैं.

उज्जैन से ग्वालियर तक चल रही जमीन की जंग

- 16 साल बाद जिला प्रशासन को दिखी उम्मीद की किरण
- महाकुंभ 2028 से पहले शासकीय जमीनों पर प्रशासन की सख्ती
- 2011 में ओंकार जिनिंग का पट्टा हुआ निरस्त

नवभारत न्यूज़

उज्जैन. सिंहस्थ महाकुंभ 2028 की तैयारियों के बीच उज्जैन में शासकीय और तकाआयमी जमीनों को लेकर जिला प्रशासन की सक्रियता बढ़ गई है. पुराने राजस्व अभिलेखों की जांच कर ऐसी जमीनों को पुन: शासन के कब्जे में लेने की कानूनी प्रक्रिया तेज की जा रही है. शहर में बेशकीमती जमीने भी इसी कड़ी का एक अहम प्रकरण बन चुकी है, जो फिलहाल राजस्व मंडल ग्वालियर न्यायालय में विचाराधीन है.

ऐसा ही एक मामला उज्जैन आगर रोड पर चरक अस्पताल के सामने स्थित ओंकार जिनिंग का भी चल रहा है, जिसमें एसडीएम एल एन गर्ग लगातार ग्वालियर जाकर ओंकार जिनिंग फैक्ट्री का फैसला जिला प्रशासन के हित में कराने के लिए प्रवास कर रहे हैं और यह जमीन यदि जिला प्रशासन को पुन: प्राप्त होती है तो यहां पर भी एक जनहित की बड़ी योजना बनाई जाएगी.

जमीनों पर फोकस-उज्जैन में महाकुंभ 2028 को देखते हुए उज्जैन जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति की मुहिम को प्राथमिकता दी है. प्रशासन का कहना है कि जिन जमीनों का राजस्व रिकॉर्ड शासन के नाम पर दर्ज है या जिनका पट्टा निरस्त हो चुका है, उन्हें दोबारा सरकारी उपयोग में लाया जाएगा. ओंकार जिनिंग को यह फैक्ट्री तकाआयमी कारखाने के लिए दी थी, जब जिला प्रशासन पूर्व में कैस जीत गया तो ग्वालियर राजस्व मंडल से फैक्ट्री संचालक को स्टे मिल गया, तब से ही दोबारा जिला प्रशासन ने केस लगाया.

प्रशासन का पक्ष- रिकॉर्ड में शासकीय

नवभारत से चर्चा में एसडीएम एलएन गर्ग ने बताया कि शासन का तर्क है कि खसरा अभिलेख स्वयं में प्रमाणित दस्तावेज होते हैं और पुराने बंदोबस्त के आधार पर स्वामित्व का दावा विधिसम्मत नहीं माना जा सकता. नवीन सर्वेक्षण बंदोबस्त लागू होने के बाद पूर्व प्रविष्टियों का स्वत: अवसान माना जाता है. इसी आधार पर शासन ने पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत की है.

रिव्यू पिटीशन दायर

ये प्रकरण राजस्व मंडल, ग्वालियर पहुंचा, जहां पूर्व संचालक पक्ष को स्थगन आदेश मिल गया. इसके चलते प्रशासनिक कब्जे की प्रक्रिया रुक गई. मामला उच्च न्यायालय तक भी गया, जहां से अंतरिम स्थगन के बाद प्रकरण पुन: अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है. वर्तमान में रिव्यू पिटीशन भी दायर की गई है.

विकास से जुड़ी संभावनाएं- यदि अंतिम आदेश जिला प्रशासन के पक्ष में आता है तो इस 3.135 हेक्टेयर भूमि पर महाकुंभ 2028 को ध्यान में रखते हुए जनहित की बड़ी योजना बनाई जा सकती है. क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहां पार्किंग, यातायात प्रबंधन केंद्र, सार्वजनिक सुविधा परिसर या अन्य आधारभूत संरचना विकसित किए जाने की संभावना जताई जा रही है.

135 हेक्टेयर जमीन का केस

ओंकार जिनिंग फैक्ट्री की लगभग 3.135 हेक्टेयर रकबे वाली यह जमीन सर्वे क्रमांक 1917 के अंतर्गत दर्ज है. पुराने खसरा अभिलेखों में इस भूमि का उल्लेख जीन प्रेस और कारखाना प्रविष्टि के रूप में मिलता है, जबकि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में इसे शासकीय प्रविष्टि से जोड़ा गया है.

2011 में पट्टा निरस्त-राजस्व दस्तावेजों के अनुसार 11 मार्च 2011 को पारित आदेश में अपर कलेक्टर स्तर से संबंधित पट्टा निरस्त करते हुए भूमि को शासन में निहित माना गया था. आदेश में मध्यप्रदेश भूमि राजस्व संहिता 1959 की धारा 182 का उल्लेख करते हुए कहा गया कि विवादित भूमि शासन की श्रेणी में आती है. इसके बाद आयुक्त स्तर पर भी आदेश को यथावत रखा गया.

अधिसूचना के एक साल पहले से ही वसूला टोल

- एमपीआरडीसी ने 43 सड़कों पर कमाये 604 करोड़

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 21 फरवरी. मप्र सड़क विकास निगम ने राज्यपाल की अधिसूचना के 6 माह से एक साल पहले ही नियमों के विपरीत गैर कानूनी टोल वसूलना शुरू कर दिया. ये कोई एक सड़क का मामला नहीं है, बल्कि ऐसे लगभग आधा दर्जन सड़कों में ऐसा किया गया.

जानकारी के मुताबिक भोपाल बायपास की अधिसूचना 8 दिसंबर 2020 को जारी हुई वहीं टोल वसूली 12 दिसंबर 2019 से शुरू कर दी गई, वहीं इंदौर- उज्जैन की अधिसूचना 30 दिसंबर 2022 को जारी हुई, वहीं टोल वसूली 21 जनवरी 2022 से शुरू कर दी गई. इसी क्रम में सागर दमोह की अधिसूचना 8 दिसंबर 21 को जारी हुई वहीं टोल वसूली 28 फरवरी 21 से ही शुरू कर दी गई. भिंड- गोपालपुरा रोड के लिए टोल वसूली की अधिसूचना 4 जनवरी 2022 को जारी हुई लेकिन टोल वसूली 19 मार्च 2021 को जारी की गई. इसी तरह गुना-ईसागढ़ की अधिसूचना 10 अक्टूबर 2024 को जारी हुई और टोल वसूली 2 लून 2023 से ही शुरू कर दी गई. महू- घाटाबिल्लोद की अधिसूचना 24 दिसंबर 2021 को जारी हुई और टोल वसूली का सिलसिला 28 फरवरी 2021 से ही शुरू कर दिया गया. इधर बीना- खिमलासा की अधिसूचना 8 दिसंबर 2021 को जारी हुई वहीं वाहनों से टोल वसूली का क्रम 19 मार्च 2021 से शुरू कर दिया गया. मप्र सड़क विकास निगम 43 सड़कों पर पिछले 2 से 3 वर्षों में दिसबंर 2025 तक 1102.15 करोड़ रूपया टोल वसूल चुका है, वहीं रखरखाव व अन्य खर्च पर महज 498.49 करोड रुपए है.

> इसी तरह एमपीआरडीसी द्वारा दिसंबर 2025 तक भोपाल बाईपास पर 284.33 करोड़, इंदौर- उज्जैन मार्ग पर 130.41 करोड़, महु-घाटाबिल्लौद पर 122.90 करोड़ तथा सागर दमोह मार्ग पर 95.59 करोड़, कुल मिलाकर 633.94 करोड़ टोल वसूला गया और रखरखाव पर 200.96 करोड़ रुपए खर्च किए गए. इन 43 सड़कों पर अवैध टोल वसूली से एमपीआरडीसी ने 603.66 करोड़ का शुद्ध लाभ प्राप्त किया.
>
> इंडियन टोल एक्ट के तहत शासन अपने स्तर पर किसी भी सड़क पर टोल नहीं ले सकता है. सड़क जनता की संपत्ति है, तथा शासन ट्रस्टी है. ट्रस्टी उस संपत्ति से बेजा लाभ नहीं कमा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने मंदसौर पुलिया के टोल प्रकरण में आदेश दिया कि कोई भी निवेशक, लागत उस पर ब्याज तथा रखरखाव के अतिरिक्त टोल नहीं वसूल कर सकता है.
>
> **प्रताप ग्रेवाल, विधायक कांग्रेस**

डिजिटल गिरफ्तारी गिरोह का भंडाफोड़, 20 गिरफ्तार

शिवपुरी. पुलिस ने साइबर अपराधों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवपुरी में सक्रिय एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस अभियान के तहत 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर 04 एफआईआर दर्ज की गईं. साथ ही लगभग 1 करोड़ 7 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई, जिसमें 29 मोबाइल फोन, 7 चार पहिया वाहन, एक मोटरसाइकिल, 1.20 लाख रुपये नकद, 7 बैंक पासबुक, 16 एटीएम कार्ड और कई सिम कार्ड शामिल हैं. यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (साइबर) ए. साईं मनोहर के निर्देशन में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन मैट्रिक्स' के अंतर्गत की गई. गिरोह महिलाओं के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों को अश्लील चैट में फंसाता था, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर 'डिजिटल गिरफ्तारी' का डर दिखाकर वसूली करता था. साथ ही क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और फर्जी लोन जैसे मामलों का भी खुलासा हुआ है. पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध कॉल या धमकी की तुरंत सूचना देने की अपील की है.

पेज एक का शेष

एसआईआर : मप्र में 34 लाख नाम हटे

राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों में अंतिम मतदाता सूची की प्रतियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध करा दी गई है.

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने शनिवार को पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने संबंधी जानकारी साझा भी की.

एसआईआर: मप्र में 34 लाख नाम हटे

की. प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई थी. ये प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में की गई. मतदाता सूची में नाम शामिल करने, विलोपित करने और संशोधित करने संबंधी दावे और आपत्ति लेने के लिए 23 दिसंबर 2027 से 22 जनवरी तक का समय तय किया गया था. चुनाव अधिकारियों ने 14 फरवरी तक दावे आपत्तियों का सत्यापन कर उनका निराकरण किया. प्रदेश के 5 करोड़ 74 लाख 6 हजार 143 मतदाताओं से से 5 करोड़ 31 लाख 31 हजार 989 मतदाताओं ने एसआईआर फार्म भरकर बीएलओ को दिए. इस दौरान बीएलओ ने घर-घर जाकर सर्वे किया, जिसके चलते दिवंगत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और दो स्थानों पर दर्ज मतदाताओं की पहचान की गई.

दावे आपत्ति के बाद 8 लाख 49 हजार 82 मतदाता और बढ़े: प्रदेश में प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 74 लाख 6 हजार 143 थी, वहीं प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद ये सूची घटकर 5 करोड़ 31 लाख 31 हजार 983 तक सीमित होकर रह गई. इस तरह इसमें 42 लाख 74 हजार 160 वोटरों के नाम शामिल नहीं हुए. ऐसे में वोटरों को नाम शामिल करने के लिए दावे- आपत्ति के माध्यम से फिर मौका दिया गया.

भाजपाई-कांग्रेसियों में भिड़ंत...

प्रथम पेज का शेष...

पुलिस ने पहले से बैरिकेडिंग कर दोनों पक्षों को अलग रखने की व्यवस्था की थी, लेकिन उग्र कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स पार करने का प्रयास किया. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने ठंडे पानी की बौछारें छोड़ीं, जिसके बाद भीड़ तितर-बितर हुई. घटनास्थल पर मौजूद अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) अमरेन्द्र सिंह और डीसीपी (जोन-3) आदित्य मिश्रा ने मोर्चा संभाला.

प्रेसवार्ता | कांग्रेस 24 से करेगी आंदोलन, राजधानी से होगी शुरुआत

अमेरिका ट्रेड डील को बताया किसान विरोधी

भोपाल, 21 फरवरी 2026. प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेसवार्ता में कांग्रेस नेताओं ने प्रस्तावित भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ गंभीर आपत्ति जताई और 24 फरवरी से भोपाल से किसान आंदोलन की शुरुआत करने की घोषणा की.

प्रेसवार्ता में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ट्रेड डील को देश और किसानों के हितों के खिलाफ करार दिया. हरीश चौधरी ने कहा कि अमेरिका द्वारा अतीत में भारत पर खाद्यान्न आपूर्ति रोकने से देश की स्थिति खराब हुई थी. उन्होंने चेतावनी दी कि प्रस्तावित डील से देश के किसानों और छोटे व्यापारियों पर गंभीर असर पड़ेगा. सोयाबीन और कपास आयात से भारतीय किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. चौधरी ने इसे भारत द्वारा अमेरिका के सामने 'सरेंडर' बताया और कहा कि कांग्रेस इस डील को ऐतिहासिक दबावों के तहत किया गया मानती है. प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भारत की कृषि स्वतंत्रता पर लगातार चोट हो रही है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे हमला करते हुए कहा कि उन्होंने देश के किसानों को अमेरिका के हाथों बेच दिया.

> उन्होंने यह भी कहा कि मध्यप्रदेश का किसान चुप नहीं बैठेगा और 24 फरवरी को भोपाल में किसान महापंचायत से आंदोलन की शुरुआत होगी. इस महापंचायत में राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी शामिल होंगे. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि यह डील देशहित में नहीं है और इसके पीछे कई संदिग्ध पहलू हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका में बने उत्पाद भारत में बेचने की तैयारी की जा रही है, जबकि भारतीय किसान अभी सम्पन्न नहीं हुआ है. उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस विधानसभा में भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाएगी. कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि किसान सम्मान निधि के तहत देश और प्रदेश के किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि डील अमेरिकी किसानों को लाभ पहुंचाने की दिशा में है. पार्टी ने कहा कि यह आंदोलन सड़क से सदन तक जारी रहेगा और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा.

भोपाल से पुणे-गाजीपुर सिटी होली स्पेशल ट्रेन

भोपाल, 21 फरवरी. आगामी होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा हेतु मध्य रेल द्वारा पुणे-गाजीपुर सिटी-पुणे स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. गाड़ी संख्या 01431 पुणे से गाजीपुर सिटी के लिए 24 एवं 27 फरवरी और 03 एवं 06 मार्च 2026 को सुबह 06:40 बजे पुणे स्टेशन से प्रस्थान करेगी.

पश्चिम रेलवे — रतलाम मंडल

वाणिज्य शाखा ई-नीलामी सूचना

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक-रतलाम मंडल - पश्चिम रेलवे ने पार्सल स्पेस की लीज के लिए ई-नीलामी आमंत्रित की है। केटलॉग को IREPS वेबसाइट (ई-ऑक्शन) पर प्रकाशित किया गया है, विवरण निम्न प्रकार से है।

केटलॉग सं. : Leasing118phas3, **अनुबंध का प्रकार** : Leasing of SLR compartment, **लॉट नं.** : Train No. 19321-SLR-R1-INDB-PNBE, 19313-SLR-F1-INDB-PNB, 19321-SLR-F1-INDB-PNBE, 22984-SLR-F1-INDB-KOTA, **अनुबंध की अवधि : 03 YEARS**, ई-नीलामी की तिथि और समय सभी लॉट के लिए ई-नीलामी **दि. 09.03.2026 को 10.00 बजे** प्रारंभ होगी। प्रारंभिक कुलिंग ऑफ अवधि 30 मिनट है। अनुक्रमिक लॉट को बंद करने का अंतराल 10 मिनट है। **IREPS** के ई-ऑक्शन मॉडयूल पर लॉटवाइज समापन समय देखा जा सकता है।

ADM/4/1/467

Follow us on: twitter.com/WesternRly

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60